भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1913

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्बों का वितरण

1913. श्री रमेश बिधूड़ीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वितरित किए गए एलईडी बल्बों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कम लागत वाला वित्तपोषण जुटाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 'सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति' (उजाला) एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसे विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिऐंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दिनांक 25.07.2016 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा लगभग 13.50 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं। राज्यवार वितरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	राज्य	वितरित एलईडी बल्ब (लाख में)
1.	दिल्ली	67.51
2.	हरियाणा	38.86
3.	हिमाचल प्रदेश	63.23
4.	उत्तराखंड	32.71
5.	राजस्थान	112.78
6.	उत्तर प्रदेश	107.84

7.	बिहार	35.96
8.	झारखंड	66.55
9.	छत्तीसगढ़	33.98
10.	महाराष्ट्र	185.82
11.	आन्ध्र प्रदेश	190.21
12.	कर्नाटक	116.14
13.	केरल	77.5
14.	पुडुचेरी	6.09
15.	गुजरात	121.98
16.	मध्य प्रदेश	38.86
17.	अंडमान व निकोबार	1.94
18.	गोआ	2.22
19.	उड़ीसा	35.1
20.	संस्थागत (रेलवे/पीएसयू)	15.1
	कुल	**1350.38**

ईईएसएल एलईडी लाइट्स को प्रोन्नत करने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जबकि अनेकों अन्य आपूर्तिकर्ता भी यहीं कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम लागत का वित्त पोषण जुटाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समन्वय में प्रमुख पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बहु-पार्श्वीय तथा द्विपार्श्वीय एजेंसियों अर्थात वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, केएफडब्ल्यू, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी इत्यादि के माध्यम में कम लागत के ऋण तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी मानदंडों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल करना समावेशित है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 5000 करोड़ रुपये के कर-मुक्त अवसंरचना बॉड भी जारी किए गए।

****